डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का बैंकों में महत्व

कृषि कुंभ (जुन, 2023),
खण्ड 03 भाग 01, पृष्ठ संख्या 62–63

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का बैंकों में महत्व

सचिन कुमार वर्मा[1] एवं योगेंद्र कुमार[2]
शोध छात्र, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवम् प्रोधोगिकी विश्वविधालय,कुमारगंज अयोध्या ,उत्तर प्रदेश[1]
परास्नातक छात्र, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश[2]
Email Id: sachinssv974@gmail.com

देश के 75 जिलों में बीते 16 अक्टूबर को डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की शुरुआत की गई. आखिर क्या होते हैं यह डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स? कैसे काम करता है और किस तरह की सुविधाएं आप उठा सकते हैं? इसे समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जब आपके जिले में इसकी (क्ठन) शुरुआत होगी तो आपको इसकी पूरी जानकारी रहे. सरकार की तरफ से आम नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग की दिशा में डीबीयू एक बड़ा कदम है. डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की मदद से छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों को लोन लेने और फंड ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी.

किस प्रकार से मिलेंगी सुविधाएं

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, एटीएम की तरह की एक मशीन होती है, जिसके जरिये आप बैंकिंग की कई सुविधाओं का फायदा खुद ही उठा सकते हैं. इस यूनिट पर कैश निकासी और जमा करा सकते हैं. इतना ही नहीं, आप अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं. अगर निवेश में रुचि रखते हैं तो फिक्स्ड डिपोजिट यानी एफडी (थ्क) या रेकरिंग डिपोजिट (त्क) करा सकते हैं. इसके अलावा डिजिटल लोन, पासबुक प्रिंटिंग, डेबिट कार्ड–क्रेडिट कार्ड सर्विस, बैलेंस पूछताछ, और फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं. आपको बैंक जाने और वहां के कर्मचारी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

बैंकों ने जगह–जगह लगाएं जा रहे हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स

तमाम बैंकों ने फिलहाल देशभार में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स मशीन सेटअप किए हैं. धीरे–धीरे देशभर में इसकी (क्पहपजंस ठंदापदह न्दपजे) संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है. इस सुविधा से वित्तीय समावेशन में काफी मदद मिलेगी. सरकार के मुताबिक,भारत के 99 प्रतिशत से ज्यादा गांवों में 5 किलोमीटर से भीतर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग कॉरेस्पोन्डेंट मौजूद हैं.डीबीयू (डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स) ग्राहकों को पूरे साल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस की सस्ती सुविधा, सुविधाजनक पहुंच और बेहतर डिजिटल एक्सपीरियंस उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगा. 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 12 निजी क्षेत्र के बैंक और एक लघु वित्त बैंक इस तरह की सर्विस में अपनी भूमिका निभा रहे हैं.

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के लाभः

- डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उन लोगों को सक्षम बनाएगा जिनके पास सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बुनियादी ढाँचा नहीं है, वे बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल रूप से एक्सेस कर सकते हैं।
- वे उन लोगों की भी सहायता करेंगे जो डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिये तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं।
- काले धन के प्रचलन में कमी
- कैशा–फ्री जाना
- आसान बिल भुगतान
- उच्च ब्याज दर/कम शुल्क
- दूरस्थ स्थानों में बैंकिंग

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की सेवाएँः

इन डिजिटल बैंकिंग इकाइयों में ग्राहकों को अपना बचत खाता खोलने, खाते में शेष राशि पता करने, पासबुक प्रिंट कराने, पैसे भेजने, सावधि जमा निवेश के अलावा क्रेडिट–डेबिट कार्ड और कर्ज के लिये आवेदन जैसे काम करने के साथ ही कर व बिलों के भुगतान की पूरी सुविधा होगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से सरकारी क्रेडिट लिंक योजनाओं और एमएसएमई/खुदरा ऋणों के एंड–टू–एंड डिजिटल प्रसंस्करण की सुविधा भी प्रदान करेंगे।

डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स और पारंपरिक बैंकों के बीच अंतरः

- डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 24 X 7 नकद जमा और निकासी सहित बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करेगा।
- डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की सेवाएँ डिजिटल रूप से प्रदान की जाएँगी।
- जिन लोगों के पास कनेक्टिविटी या कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं हैं, वे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स से पेपरलेस मोड में बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं।
- बैंक कर्मचारी सहायता प्राप्त मोड में बैंकिंग लेनदेन के लिये उपयोगकर्त्ताओं की सहायता और मार्गदर्शन के लिये उपलब्ध रहेंगे।
- डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रदान करने और डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिये जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा।

डिजिटल बैंकों और डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बीच अंतरः

- बैलेंस शीट/कानूनी मान्यता
- डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के पास कानूनी मान्यता नहीं है और उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लाइसेंस नहीं दिया गया है।
- कानूनी रूप से वे ''बैंकिंग आउटलेट'' अर्थात शाखाओं के समकक्ष हैं।
- डिजिटल बैंकों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत विधिवत लाइसेंस प्राप्त एक बैंक है, जिनके पास एक बैलेंस शीट और कानूनी अस्तित्व है।

नवाचार/प्रतिस्पर्द्धा का स्तरः

- डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स डिजिटल चौनलों को नियामक मान्यता प्रदान करके मौजूदा चौनल बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करते हैं। हालाँकि, वे प्रतिस्पर्द्धा पर चुप्पी साधे हुए हैं।
- डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स दिशा–निर्देश स्पष्ट रूप से बताते हैं कि केवल मौजूदा वाणिज्यिक बैंक डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित कर सकते हैं।
- इसके विपरीत यहाँ प्रस्तावित डिजिटल बैंकों के लिये लाइसेंसिंग और नियामक ढाँचा प्रतिस्पर्द्धा/नवाचार आयामों के साथ अधिक सक्षम है।

डिजिटल बैंकिंग का महत्व

डिजिटल बैंकिंग आपको अधिक वैयक्तिकृत बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है। विशिष्ट बैंकों की कुकी–कटर सुविधाओं के विपरीत, डिजिटल बैंकिंग बिल भुगतान रिमाइंडर, व्यक्तिगत बजट, धन प्रबंधन, बड़ी खरीद बचत आदि जैसी सुविधाएँ प्रदान कर सकती है।

संक्षेप में

जबकि भारत में डिजिटल बैंकिंग में अभी भी कई बाधाएं हैं, इसे दूर करना होगा, यह एक लंबा सफर तय कर चुका है। डिजिटल बैंकिंग का भविष्य निश्चित रूप से हमेशा अपनी सीटों के किनारे पर है। एक बचत खाता खोलना, एफडी बनाना, एक एसआईपी शुरू करना, और कई अन्य चीजें अब आपके मोबाइल पर की जा सकती हैं जिसके लिए एक समय में आपको अंतहीन फॉर्म भरने पड़ते थे। निकट भविष्य में एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग उपस्थिति वाला भारत अपरिहार्य प्रतीत होता है।